स्तरण स्थलों पर दबाव कम हो जायेगा जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को खाद्यान्नों की सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हो जायेगा। स्टाकयार्डों को नमक, सीमेंट और इस्पात की ढुलाई करने से मीटर लाइन पर भी फालतू क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। मीटर लाईन प्रणाली पर उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग सामान्य खपत की अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जा सकेगा। रेलों को आशा है कि इन उपायों से इस क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताएं संतोषप्रद स्तर तक पूरी हो जाएंगी।

Decentralisation of Railways

8449. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a proclaimed policy of Government to decentralise the working of the Railways;

(b) whether the transfers of Directors and Deputy Director from Zonal Railways to the Railway Board offices in Delhi are in consonance with that policy;

(c) whether these senior officers are engaged in monitoring the day to day operations and maintenance works of the Railways; and

(d) whether this work was previously looked after by the Commercial Departments of various Zonal Officers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes. The policy is to achieve maximum possible decentralisation.

(b) There are no Directors or Deputy Directors in Zonal Railways. Officers from Railways are posted as Directors, etc., in Railway Board on deputation.

(c) Yes.

(d) No.

कैरिज एण्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारी

8450. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कैरिज काउंसिल के आह्वान पर कुछ महीने पहले कैरिज एण्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारियों को देश भर में नियमानुसार कार्य आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के संबंध में अनेक कर्मचारियों को दंडित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो दण्डित किये गये कर्मचारियों की जोन वार संख्या क्या है ; और

(घ) इन कर्मचारियों को दोष मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि इन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(क) से (घ) आल इंडिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ काउंसिल ने, जो एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, अपनी मांग मनवाने में कथित असफलता के कारण 16-8-80 से "नियमानुसार कार्य" करने का अवैध आन्दोलन शुरू किया था। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई थी :—

पूर्वोत्तर रेलवे

बर्खास्त किये गये/सेवा से हटाये गये	4
निलंबित	17 (12 को वापस ड्यूटी पर रख लिया गया)
सेवा भंग का दंड	12
मजूरी काटने का दंड	152
चेतावनी	18
अन्य अनुशासिनक कार्रवाई	21

पूर्व रेलवे

मजूरी काटने का दंड	12,934
सेवा भंग करने का दण्ड	366

दक्षिण मध्य रेलवे

मजूरी काटने का दंड	30

नियमानुसार कर्मचारी को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है, जिनका उस के वेतन, भत्तों, पेन्शन भविष्य निधि, सेवा उपदान अथवा नियमों अथवा करार आदि में विनियमित अन्य सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर किया जाता है।

Fly Overs Under Construction for Asian Games

8451. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether some experts participating in the group-discussion on the effects of New Construction on Delhi's Environment at the India International Centre on the 4th March, 1981 have pointed out that the seven fly-overs under construction in the city as part of the new infrastructure for the 1982 Asian Games will be an expensive alternative to traffic control manual or electronical as reported in the 'Hindustan Times' dated 5th March, 1981;

(b) if so, the reaction of the Government thereto; and

(c) the extent of damage done by feling of trees as a prelude to the proposed construction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) It is not correct to say that the construction of seven flyovers will be an expensive alternative to manual or signalised traffic control. A traffic study carried out by experts has revealed that the projected normal peak hourly traffic in 1982 is going to be beyond the capacity of both manual and signalised traffic control measures. There is no other option but to go in for grade separation at these seven intersections. The improvement of these junctions was already included in the 6th Plan (1978—83) of Delhi Administration.

(c) Only those trees which have to be inescapably removed due to construction of the flyovers or those which cannot be transplanted are being cut. Further, it is proposed to plant new quick-growing trees to the extent of at least double the number of cut trees so that present environment is maintained.

Confirmation of Clerks

8452. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Northern Railway Adminstration issued orders sometime in 1980 about the regularisation and confirmation of clerks Grade Rs. 260—400 (Revised Scale) who were recruited in 1975 on an ad-hoc basis.